

2



चरनोई भूमि से चार स्थलों से अतिक्रमण

5



स्कूल शिक्षिका से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर

8



देश के प्रतिष्ठित खेल पत्रकार और एंकर हैं विकास गुप्ता

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 24

प्रति सोमवार, 21 अक्टूबर 2024

मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

छत्तीसगढ़ सरकार की एक और पहल

समर्थ और सशक्त समाज के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी मुख्यमंत्री साय की महतारी सदन बनाने की पहल

किसी भी सशक्त समाज की परिकल्पना वहां की महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण उपरांत ही का जा सकती है। जब तक समाज की महिलाएं सबल नहीं होती तब तक

कवर स्टोरी

-विजया पाठक

एडिटर

राज्य को सबल और आत्मनिर्भर नहीं माना जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक

नई पहल शुरू करते हुए राज्य की महिला सरपंचों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री का यह कदम निश्चित ही महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सबल तो बनायेगा ही साथ ही एक सशक्त समाज की नींव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।



अगर हम अभी तक महिलाओं की स्थिति पर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान महिलाएं पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर थीं, कामकाज का इतना अभाव था कि महिलाओं को दो

वक्त की रोटी जुटाने के लिये भी संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन साय सरकार में महिलाओं को संघर्ष से छुट्टी मिली है और वह अब स्वयं ही अपना कार्य करने में जुट गई है। महिलाओं के प्रति मुख्यमंत्री की यह संवेदनशीलता ही एक आत्मनिर्भर समाज की परिकल्पना को साकार करने में सहायक होगी।

महतारी सदन बनाने की पहल

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने गांवों के विकास में गांव की महिलाओं को भागीदार बनाने के लिए एक अनूठी पहल करते हुए ग्राम सचिवालय की तर्ज पर ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाने की पहल को आगे बढ़ाया है। जिस प्रकार गांव के विकास की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में ग्राम सचिवालय अहम भूमिका निभाता है, उसी प्रकार महतारी सदन से महिलाओं को आत्मनिर्भर

बनाने वाली योजनाओं का संचालन होगा। साथ ही महतारी सदन से गांव के विकास में महिलाएं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने ग्राम पंचायतों में 25 सौ वर्ग फुट के आकार वाले महतारी सदन बनाने की पहल की है। इसके लिए सभी जरूरी सुविधाओं से लैस 179 महतारी सदन बनाने की स्वीकृति देते हुए आवश्यक बजट राशि भी जारी कर दी गई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गांवों में वूमन एम्पावरमेंट स्कीम का कुशल संचालन करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में महतारी सदन का निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। शर्मा ने शुरू में 179 महतारी सदन बनाने की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि नए भारत के विकास में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

(शेष पेज 3 पर)

विष्णुदेव सरकार के राज में छत्तीसगढ़ की जनता को आखिर कब मिलेगा न्याय?

कांग्रेस की भय-भ्रष्टाचार-दमन-अत्याचार की 05 साल की सरकार के मुख्य साजिशकर्ताओं पर कब होगी कार्यवाही?

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की भूपेश राज वाली भय-भ्रष्टाचार-दमन-अत्याचार वाली सरकार का अंत हुए अब कोई 10 महीने हो गए हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है आखिर कब होगा न्याय। महादेव सट्टा घोटाला, शराब घोटाला, कोयला या डीएमएफ घोटालों के पर्दे के पीछे के असली मास्टरमाइंड आखिर कब जेल जाएंगे। इन सभी घोटालों के तार तब के मुख्यमंत्री और उनके करीबियों तक जाते थे, पर अभी तक उन पर कोई ठोस कार्यवाही होती नहीं दिख रही है। अलबत्ता सरकार का ईओडब्ल्यू और एसीबी विभाग सिर्फ प्यादों पर कार्यवाही करने में लगा है बस एक एफआईआर करके पूर्व मुख्यमंत्री को अभयदान दे दिया गया है। (शेष पेज 7 पर)

मोहन सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल कांग्रेस के दिग्गज बैठे सामूहिक उपवास पर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश में हुए सक्रिय

-विजया पाठक

प्रदेश में महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जिनको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश में महिलाओं, बच्चियों पर लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं जिसे लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं ने एक अलग तरीके सरकार को घेरने की कोशिश की है। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे में कांग्रेसियों ने सामूहिक उपवास शुरू किया है। इस उपवास में कांग्रेस के सभी बड़े नेता पहुंच कर एकता का संदेश दिया है। जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कांग्रेस के सभी जिलों के नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। (शेष पेज 7 पर)





महिलाओं पर हो रहे अपराधों के विरोध में कांग्रेस का उपवास

-अर्चना शर्मा

जगत प्रवाह. भोपाल। प्रदेश में बेटियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अपराध की बढ़ती घटनाओं व प्रदेश को ड्रग माफिया का अड्डा बनाए जाने के खिलाफ मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रांत व्यापी उपवास कार्यक्रम का आयोजन रोशनपुरा चौराहे पर किया जा रहा है। उपवास कार्यक्रम को सागर जिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रेखा चौधरी,

इंदौर की युवा नेत्री नेहा लिंबोदिया आदि समेत प्रदेश भर से आई महिला नेत्रियों ने संबोधित किया। संचालन महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने किया। उपवास कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह

राहुल भैया, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री डॉ विजय लक्ष्मी साधो, कमलेश्वर पटेल, सुखदेव पांसे, मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक, डॉ संदीप सबलोक, आनंद जाट, जितेंद्र मिश्रा समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक व कार्यकर्ताओं की लगातार हिस्सेदारी हो रही है। (जगत फीचर्स)

ताशू राजपूत और रंजीता धुर्वे का यूनिवर्सिटी के लिये चयन

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। कबड्डी कोच

अंकित जोशी ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आयोजित होना है जिसके लिए टिमरनी कॉलेज की ताशू राजपूत रंजीता धुर्वे बरकतउल्ला विश्वविद्यालय टीम के लिए हुआ है। दोनों खिलाड़ी इसके पहले भी यूनिवर्सिटी टीम का हिस्सा रह चुके हैं इन दोनों खिलाड़ी के अलावा टिमरनी की विशाखा कलोसिया का चयन भी टीम में हुआ है। इस उपलब्धि पर नर्मदा खेल अकादमी के अध्यक्ष संजय शाह कबड्डी क्लब के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र भारद्वाज सुनील दुबे कैलाश डूडी जन भागीदारी अध्यक्ष उपेंद्र गादरे प्राचार्य जैन सर जगदीश शर्मा मंगल सिंह यादव रामनिवास जाट अरुण वर्मा पंकज तिवारी रामजीवन गोदारा राजकुमार चंदेल हिना अली खान नीतिका बोरारी नितेश कनाटे सुरेश बघेल रोहित रहड़वा धनरालाल जाट विजय सावनेर प्रियंका चंदेल ने बधाई दी। (जगत फीचर्स)



एमएस भोपाल के डॉ. दानिश जावेद को "रियल-टाइम माइक्रोबियल डिटेक्शन ग्लव्स" के लिए यूके पेटेंट प्राप्त

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. भोपाल।

एमएस भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में आयुष विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. दानिश जावेद को "रियल-टाइम माइक्रोबियल डिटेक्शन ग्लव्स" के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित यूके पेटेंट से सम्मानित किया गया है। इस नवाचार को यूके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस द्वारा मान्यता दी गई और 14 अक्टूबर, 2024 को आधिकारिक रूप से पेटेंट प्रदान किया गया। रियल-टाइम माइक्रोबियल डिटेक्शन ग्लव्स को स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा को बढ़ाने

और हानिकारक रोगाणुओं की त्वरित पहचान के लिए डिजाइन किया गया है। यह पेटेंट तकनीक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, विशेष रूप से उन जगहों पर जहां रोगाणुजनित संक्रमण का अधिक जोखिम होता है। इन ग्लव्स के विकास में कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का सहयोग शामिल है, जिनमें सरुदी अरब के डॉ. राजी कलियापेरुमल, थाईलैंड के प्रोफेसर डॉ. पोंगकिट



एकवितायावेचनुकुल और भारत से डॉ. दानिश जावेद, लोवलेश गुप्ता, डॉ. राहुल तिवारी, डॉ. हिना दीक्षित तिवारी, और बिमल देबबर्मा शामिल हैं। यह पेटेंट अंतरराष्ट्रीय डिजाइन वर्गीकरण के क्लास 02, सबक्लास 06 के तहत आता है, जो वस्त्र और परिधान से संबंधित है। एमएस भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने इस उपलब्धि पर टीम को बधाई देते हुए कहा, "यह उपलब्धि एमएस के डॉक्टरों की चिकित्सा नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण का प्रमाण है। 'रियल-टाइम माइक्रोबियल डिटेक्शन ग्लव्स' न केवल स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा को बढ़ाते हैं, बल्कि संक्रमण नियंत्रण उपायों में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें उम्मीद है कि यह तकनीक चिकित्सा क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालेगी।" यूके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस द्वारा इस नवाचार की मान्यता एमएस भोपाल की चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने और अत्याधुनिक स्वास्थ्य समाधानों के विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह पेटेंट अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक चिकित्सा प्रगति में संस्थान के योगदान का प्रतीक है। (जगत फीचर्स)

हकीकत से कोसो दूर है केंद्र सरकार द्वारा जारी किये आंकड़े

सरकारें आती हैं, जाती हैं लेकिन बगैर कुछ किये ही कम होते बेरोजगारी दर के जादूगरी दिखाते आंकड़े

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश और देश के लिये बढ़ती मंहगाई और बेरोजगार युवा यह दोनों ही चिंता का विषय है। भले ही हम विभिन्न सर्वे रिपोर्ट के आधार पर समाचार पत्रों और टेलीविजन में यह देख खुद को कुछ समय

के लिये सांत्वना दें ले कि मंहगाई और बेरोजगारी दर धीरे-धीरे कम हो रही है। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। बात चाहे मध्यप्रदेश की हो या पूरे देश की। आज के समय में बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ा चिंता का विषय भी है और

चुनौती का भी। चिंता का विषय इसलिये क्योंकि एक के बाद एक सत्ताधारी दल सत्ता का सुख भोगकर यहां से चले जाते हैं लेकिन न तो बेरोजगारी दर में कोई कमी होती दिख रही है और न ही बेरोजगारों की संख्या में कमी। (शेष पेज 3 पर)

चरनोई भूमि से चार स्थलों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह. विदिशा।

कलेक्टर रौशन कुमार सिंह के द्वारा जिले में चरनोई भूमि को अतिक्रमण से विमुक्त कराने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर सिंह के द्वारा सभी राजस्व अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश पूर्व में ही जारी किए गए हैं। हर रोज चरनोई भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही राजस्व अधिकारियों के द्वारा विशेष तौर पर संपादित की जा रही है। विदिशा तहसील के अंतर्गत ग्राम भाटखेडी में सम्पन्न की गई कार्यवाही संबंधी जानकारी देते हुए एसडीएम क्षितिज शर्मा ने बताया कि भूमि सर्वे नम्बर 188 चरनोई मद की भूमि से अतिक्रमण हटवाने के कार्य किए गए हैं। नायब तहसीलदार श्रीमती निधि पटेल ने बताया कि चरनोई की उक्त भूमि के कुछ भाग पर अतिक्रमणकर्ता शफीक खां, गजराज सिंह, लईक खां, बृजेश शर्मा द्वारा फसल लगाकर अतिक्रमण किया गया था जिसे आज अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्यवाही की



गई है। विदिशा ग्रामीण तहसीलदार अजय पाठक ने बताया कि ग्राम पीपलखेडा अंतर्गत खसरा नम्बर 368/2 रकवा 5.516 में से 4.553 हेक्टेयर मुक्त कराया गया है उक्त चरनोई भूमि पर टीकाराम, द्वारकादास, दिनेश दास, चरण सिंह, भैयालाल, तुलसीराम, सीताराम, काशीराम के द्वारा

अतिक्रमण को हटाया गया है। बासौदा एसडीएम विजय राय ने बताया कि बासौदा तहसील के ग्राम ककरावादा में भी शुकवार को शासकीय भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया गया है यहां राजस्व व पुलिस अधिकारियों के संयुक्त समन्वय से ककरावादा में शासकीय भूमि खसरा नम्बर 216 रकवा 3.428 हेक्टेयर को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि की वैल्यू लगभग 68 लाख रूपए आंकलित की गई है। इसी प्रकार बासौदा अनुविभाग क्षेत्र में ही एसडीएम विजय राय, एसडीओपी मनोज मिश्रा के संयुक्त दल द्वारा ग्राम सिरनोटा तहसील त्योंदा में स्थित शासकीय चरनोई भूमि सर्वे क्रमांक 633 रकवा 1.275 हेक्टेयर को भी राजस्व व पुलिस प्रशासन के संयुक्त उपस्थिति में निर्विघ्न रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही संपादित की गई है। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि की वैल्यू लगभग 32 लाख रूपए आंकलित की गई है। (जगत फीचर्स)

अपराधों पर नियंत्रण के लिए की जाए सख्ती से कार्यवाही: सीएम साय

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर सख्ती से कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि हर हाल में कानून और व्यवस्था बहाल रखना चाहिये। पुलिस त्वरित कार्यवाही करे और चौकन्ना रहे। बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर होने वाली घटनाओं पर पुलिस की पैनी नजर होनी चाहिए और इन घटनाओं के संभावित परिणाम पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधों को रोकने के लिए नशे के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जाए। गांजा, अवैध शराब, ड्रग्स की तस्करी पर मुसौदों से कार्यवाही हो। सीएम साय

ने कहा कि, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि में पुलिस की गश्त नियमित रूप से होनी चाहिए। पुलिस के आला अफसर भी अनिवार्य रूप से पेट्रोलिंग करें। रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डों के साथ ही संवेदनशील इलाकों में नियमित रूप से पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहनी चाहिए। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल, दुकानों, होटलों आदि रात्रि के समय पर निर्धारित समय पर बंद होनी चाहिए। बियर बार एवं होटल निर्धारित समय पर बंद हो ऐसे होटल जहां शराब की अवैध बिक्री की शिकायत मिलती है उन पर सख्त कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सायबर क्राइम को रोकने के लिए तत्परता से प्रभावी कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। (जगत फीचर्स)

रायपुर दक्षिण सीट से बीजेपी के सुनील सोनी होंगे उम्मीदवार

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायपुर। बीजेपी के सीनियर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल की परंपरागत विधानसभा सीट रायपुर दक्षिण के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को ब्रजमोहन अग्रवाल का राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना है। बीजेपी ने ब्रजमोहन अग्रवाल की पसंद का ध्यान रखा। सुनील सोनी, ब्रजमोहन अग्रवाल के करीबी माने जाते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर ब्रजमोहन अग्रवाल की लोकप्रियता को धुनाने के लिए बीजेपी ने सुनील सोनी को उम्मीदवार बनाया। रायपुर दक्षिण सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी। अभी तक यह सीट भाजपा के प्रभावशाली नेता ब्रजमोहन अग्रवाल के पास थी। आठ बार विधायक रहे अग्रवाल 1990 से विधानसभा चुनाव में अजेय रहे। भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में अग्रवाल को रायपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था। वह पहली बार सांसद चुने गए हैं। टिकट की घोषणा होने के बाद सुनील सोनी सबसे पहले ब्रजमोहन अग्रवाल से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। सुनील सोनी पहली बार 2019 में रायपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। सोनी रायपुर नगर निगम के महापौर रह चुके हैं। वह रायपुर विकास

प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सुनील सोनी को टिकट देकर बीजेपी ने एक साथ कई दांव खेले हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने सुनील सोनी का टिकट काट कर ब्रजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया। टिकट कटने के बाद भी सुनील सोनी ब्रजमोहन अग्रवाल के लिए जमकर प्रचार किया। सोनी ने पार्टी लाइन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और रायपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत के लिए जमकर मेहनत की। ऐसे में पार्टी ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट दिया है। बीजेपी ने सांसदों का टिकट काटकर विधायकी का टिकट दिया है।

ब्रजमोहन अग्रवाल की पसंद पर लगी मुहर

जातिगत समीकरण को भी साधा- रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने यहां से ऐसे उम्मीदवार को उतारा जो जातिगत समीकरण पर भी फिट बैठता हो। सामान्य वर्ग के वोटों को साधने के लिए सुनील सोनी को टिकट दिया गया है।

सरल व सहज नेता की छवि- सुनील सोनी कई अहम पदों पर रहे हैं लेकिन उनके छवि सरल व सहज नेता की है। मेयर, सांसद और रायपुर विकास प्रधिकरण का अध्यक्ष होने के बाद भी वह किसी तरह के विवादों में नहीं रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने जनता को यह संकेत देने की कोशिश की है कि उसने एक साफ छवि के नेता का टिकट दिया है।

समर्थ और सशक्त समाज के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी मुख्यमंत्री साय की महतारी सदन बनाने की पहल

(पेज 1 का शेष)

छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों में बनने जा रहे महतारी सदन भी इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने और उन्हें कामकाज के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए गांवों में महतारी सदन बनाए जा रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महतारी सदन का डिजाइन तैयार किया गया है। इसके मुताबिक एक महतारी सदन बनाने की लागत 29.20 लाख रुपये होगी। इसके लिए महतारी सदन योजना के बजट से 24.70 लाख रुपये तथा स्वच्छ भारत मिशन के बजट से 4.50 लाख खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार 179 महतारी सदन हेतु 52 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

05 साल में हर गांव में होगा महतारी सदन

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत प्रदेश के 179 विकासखंड में महतारी सदन बनाने से गयी है। अगले 5 साल के दौरान सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगभग 25 सौ वर्गफुट जमीन पर महतारी सदन बनाया जाएगा। इसमें कमरा, शौचालय, बरामदा, हाल, किचन और स्टोर रूम बनाए जाएंगे। इसमें पानी की आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वैस्टिंग का भी इंतजाम किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से महतारी सदन के चारों ओर बाउंड्री भी बनाई जाएगी।

योजना को एक नजर में देखें

- 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायतों में होगा निर्माण।
- 688 पंचायतों में तीन हजार से अधिक लोग निवासरत।
- 202 पंचायतों में महतारी सदन का पहले चरण में निर्माण।
- 50 करोड़ रुपये मिल चुका है विभाग को।
- 29.20 लाख का प्रावकलन किया गया है तैयार।

हकीकत से कोसो दूर हैं केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गये आंकड़ों की यह रिपोर्ट

(पेज 2 का शेष)

और चुनौती का विषय इसलिये भी क्योंकि बढ़ती जनसंख्या में अगर भारत में बेरोजगारों के हाथों में रोजगार नहीं आया तो दिन प्रतिदिन अपराधों की संख्या में इजाफा होता चला जायेगा और इसे रोक पाना बहुत बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं कि आखिर यह विषय आज प्रासंगिक क्यों है। इसका कारण है कि पिछले दिनों मध्यप्रदेश के संदर्भ में एक बेरोजगारी दर पर केंद्रित सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रिपोर्ट को पढ़ने के बाद दिमाग और दिल दोनों ही हिल गये। रिपोर्ट में बड़े ही स्पष्ट ढंग से लिखा है कि मध्यप्रदेश में बेरोजगारी दर पूरे देश की तुलना में महज 1 प्रतिशत कम है। अब यह सर्वे कितना सही और कितना झूठ है यह तो समय बतायेगा लेकिन फिलहाल सर्वे के आधार पर कुछ समय यह कहकर खुश हुआ जा सकता है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर कम होती दिखाई दे रही है। अब बात करें राष्ट्रीय स्तर की तो दुनिया में किसी भी देश के विकास में बेरोजगारी एक जटिल अवरोध है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले हमारे देश भारत में बेरोजगारी और भी बड़ी चुनौती है। देश के अंदर 49.6 प्रतिशत लोग रोजगार संबंधी कारणों से पलायन करते हैं। वहीं, देश के हृदय प्रदेश के रूप में विख्यात मध्यप्रदेश से भी बड़ा पलायन होता है। यहां से 50.9 प्रतिशत लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। बेरोजगारी की वजह से मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों से देश के अलग-अलग हिस्सों में पलायन होता है। प्रदेश के इन जिलों में एक नाम सागर का भी है। सागर प्रदेश का मध्यस्थ क्षेत्र और बुंदेलखंड का अहम हिस्सा है। सागर में काफी पिछड़ापन है। जिसकी प्रमुख वजह है यहां औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार ना होना। वहीं सागर के ग्रामीण इलाकों में और भी प्रचंड बेरोजगारी है। जिसकी वजह है संसाधनहीनता या रोजगार के पर्याप्त साधन न होना।

क्या कहते हैं बेरोजगारी दर के आंकड़ें?

एक नजर जब हम बेरोजगारी के आंकड़ों पर डालते हैं, तब फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट में बेरोजगारी के इतिहास का जिक्र हमें मिलता है। फोर्ब्स का डेटा बताता है कि, जनवरी, 2024 में बेरोजगारी दर 6.57 प्रतिशत थी। वहीं वर्ष 2023 में 8.003 प्रतिशत रही। वर्ष 2022 में बेरोजगारी दर 7.33 प्रतिशत और वर्ष 2021 में 5.98 प्रतिशत थी। जबकि, 2020 में बेरोजगारी दर 8.00 प्रतिशत रही। ऐसे में वर्तमान वर्ष 2024 से एक दशक पीछे देखा जाए तब वर्ष 2014 में बेरोजगारी दर 5.44 प्रतिशत थी। इससे भी पीछे देखा जाए तब मालूम होता है कि, 2008 में बेरोजगारी दर 5.41 प्रतिशत रही थी। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट यह भी बताती है कि, जनवरी 2024 में बेरोजगारी दर पिछले 16 महीनों में सबसे कम रही है। हालांकि, 20 से 30 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर में 2023 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर बढ़कर 44.49 प्रतिशत हो गई थी।

एक अन्य रिपोर्ट में भी हुआ बेरोजगारी दर का उल्लेख

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के कुल बेरोजगारों में 80 फीसदी युवा हैं। 'द इंडिया इंप्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024' के मुताबिक पिछले करीब 20 सालों में भारत में युवाओं के बीच बेरोजगारी लगभग 30 फीसदी बढ़ चुकी है। साल 2000 में युवाओं में बेरोजगारी दर 35.2 फीसदी थी जो 2022 में बढ़कर 65.7 फीसदी हो गई। भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा बहुत व्यापक है। देश में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अब जरा सरकारी आंकड़े देखिये सरकारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर एक फीसदी से भी कम है। केरल

और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में युवा बेरोजगारी दर ज्यादा है। वहीं, मध्य प्रदेश और गुजरात में सबसे कम बेरोजगारी दर है। जारी आर्थिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से पता चला है कि केरल में 15-29 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 29.9% है, जिसमें महिलाओं में बेरोजगारी दर 47.1% और पुरुषों में 19.3% है। पीएलएफएस (पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे) के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% पर अपरिवर्तित रही, जबकि महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर पिछले वर्ष के 2.9% से बढ़कर 3.2% हो गई। युवा बेरोजगारी दर दोहरे अंकों में 10.2% थी, जिसमें महिलाओं में यह दर 11% और पुरुषों में 9.8% थी। 2022-23 में 15-29 आयु वर्ग के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 10% थी।

केंद्र शासित प्रदेशों का हाल

केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 15-29 वर्ष आयु वर्ग में सबसे अधिक बेरोजगारी दर के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जहां महिलाओं में बेरोजगारी दर 79.7% और पुरुषों में 26.2% दर्ज की गई है। इसके बाद एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप है, जहां बेरोजगारी दर 33.6% है। महिलाओं में बेरोजगारी दर 49.5% और पुरुषों में 24% थी।

पूर्वांतर के राज्यों में भी बढ़ी

नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी युवा बेरोजगारी दर उच्च दर्ज की गई, जबकि गोवा में यह दर 19.1% थी। आंकड़ों से यह भी पता चला कि जुलाई 2023-जून 2024 की अवधि में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बेरोजगारी दर दोहरे अंकों में थी। शहरी क्षेत्रों में, कुल युवा बेरोजगारी दर 14.7% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 8.5% से कम थी। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में कुल बेरोजगारी दर 20.1% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह 8.2% थी।

सम्पादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल और उसके मायने

लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो क्षेत्रीय दलों का सहयोग लेना पड़ रहा है। सरकार के कुछ निर्णयों को संसद में तत्काल पारित कर लागू करने के बजाय संसदीय समिति आदि से विस्तृत विचार और जरूरत होने पर संशोधन के लिए रख दिया गया। लेकिन इस रुख से प्रधानमंत्री को कमजोर तथा सरकार पांच साल नहीं चल सकने के दावे करके देश विदेश में भ्रम पैदा किया जा रहा है। जबकि अब लोकसभा और राज्य सभा में भी पर्याप्त बहुमत होने से सरकार महत्वपूर्ण विधेयक पारित करवा सकेगी। संविधान में बड़ा संशोधन किए बिना सरकार सामाजिक आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर क्रान्तिकारी बदलाव के फैसले संसद से पारित कर लागू कर सकती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक की सरकारों के कार्यकाल का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो यह साबित हो सकता है कि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी ने सर्वाधिक साहसिक फैसले किए। पहला परमाणु परीक्षण हो या बैंकों और कोल इंडिया का राष्ट्रीयकरण या 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद बांग्ला देश का निर्माण, क्या कमजोर नेतृत्व की सरकार से संभव था। उन निर्णयों को गलत कहने वाले लोग रहे हैं। हां इमरजेंसी बहुत बड़ी राजनीतिक गलती थी, लेकिन यह प्रधानमंत्री के कमजोर होने की परिणति थी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने, तलाक व्यवस्था विरोधी कानून, संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान का आरक्षण, ब्रिटिश राज के काले कानूनों के बजाय नई न्याय संहिता लागू करने जैसे क्रान्तिकारी बदलाव अपने दृढ़ संकल्प और पर्याप्त बहुमत के बल पर किए। आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री इतने बड़े कदम नहीं उठा सके। इससे पहले 1967 (इंदिरा गांधी), 1977-1979 (मोरारजी देसाई और चरण सिंह), 1989-1991 (वी पी सिंह, चंद्रशेखर), फिर 1999 तक नरसिंहा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवेगौड़ा इंद्रकुमार गुजराल तक की कमजोर सरकारों से कोई बड़े निर्णय नहीं हो सके। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी

और मनमोहन सिंह की गठबंधन की सरकारों में खींचातानी, घोटालों की मजबूरियों से न केवल राजनीतिक पतन बल्कि आर्थिक विकास में कठिनाइयां आईं। गठबंधन के कारण वाजपेयी और मनमोहन सिंह को कई क्षेत्रीय नेताओं के दबाव और भ्रष्टाचार को झेलना पड़ा। इसे राजनीतिक चमत्कार ही कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के दस वर्षों के कार्यकाल में किसी एक मंत्री के विरुद्ध घोटाले का कोई प्रामाणिक आरोप सामने नहीं आ सका। राहुल गांधी या अन्य विरोधी नेता सरकार पर अनेक आरोप लगाते रहे, फिर भी जनता ने तीसरी बार मोदी की सरकार बनवा दी। केंद्र से अधिक राज्यों में कमजोर मुख्यमंत्रियों तथा दल बदल की अस्थिर सरकारों से राजनीति से अधिक नुकसान सामाजिक और आर्थिक विकास में हुआ। दिलचस्प बात यह है कि 1956 में केरल से दलबदल की शुरुआत हुई और बहुमत वाली कांग्रेस को धक्का लगा। इसके बाद तो केरल में कम्युनिस्ट पार्टियों, मुस्लिम लीग और स्थानीय पार्टियों के गठबंधन की सरकारें तथा कांग्रेस गठबंधन की दोस्ती दुश्मनी का खेल चलता रहा। वह आज भी जारी है। राज्य और केंद्र में दोनों के चेहरे या मुखौटे अलग-अलग हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता के लिए भ्रम जाल ही कहा जा सकता है। हाल के चुनाव में भी राहुल गांधी के विरुद्ध मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया, पश्चिम बंगाल में भी यही किया। जबकि केंद्र के लिए बने कथित गठबंधन में साथ रणनीति बनाते रहे। दुनिया में ऐसा राजनीतिक मजाक और धोखा शायद ही देखने को मिले। उनके लिए सत्ता का खेल है, लेकिन इस तरह की स्थितियों से केरल अन्य पड़ोसी दक्षिण के राज्यों से आर्थिक विकास में पिछड़ता गया। साक्षरता में अग्रणी और योग्य लोगों को बड़ी संख्या में खाड़ी के देशों में नौकरी तथा अन्य काम धंधों के लिए दुनिया भर में जाना पड़ा। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में हुई, जहां कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, तृणमूल कांग्रेस के माया जाल से सत्ता के दशक तक रहे उद्योग धंधे भी बर्बाद हुए और टाटा बिड़ला जैसे उद्योगपति तक अपने उद्योग अन्य राज्यों में ले गए।

सियासी गहमागहमी

कहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में तो नहीं राजेन्द्र शुक्ला



मध्यप्रदेश में भले ही डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की कमान पार्टी आलाकमान ने सौंपी है। लेकिन लगातार पार्टी और उसके बाहर इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या सच में आलाकमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कामकाज से संतुष्ट है या नहीं। यही कारण है कि पार्टी आलाकमान गुपचुप तरीके से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल पार्टी और प्रदेश सरकार के कामकाज की गुप्त रिपोर्ट मांगता रहता है। इस बात का खुलासा तो तब हुआ जब पार्टी के एक वरिष्ठ नेता पिछले दिनों प्रदेश के प्रवास पर पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा के दौरान वह यह बैसे कि प्रदेश में जल्द ही शीर्ष स्तर पर बड़े बदलाव की संभावना है इसी बीच नेता जी के मुंह से यह निकल गया कि उप मुख्यमंत्री शुक्ल को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उसके बाद से ही शुक्ल से समर्थक फूले नहीं समां रहे हैं और हर स्थान पर उनकी ब्रांडिंग का कार्य जारी है।

शिवराज के उत्तराधिकारी बनेंगे भागव

विदिशा विधानसभा सीट से लोकसभा सांसद बनने के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव



होना लंबित था। चुनाव आयोग ने पिछले दिनों चुनाव की घोषणा की। इसके साथ ही बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर चुनाव आगामी दिनों में होना है। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रमुख मानी जा रही बुधनी विधानसभा सीट से रमाकांत भागव को टिकट मिला है। ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि शिवराज के असली उत्तराधिकारी उनके बेटे कार्तिकेय नहीं बल्कि रमाकांत भागव बने हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भागव को टिकट दिलवाकर तीन साल बाद आगामी चुनाव में शिवराज सिंह चौहान क्या खेल खेलते हैं यह तो समय ही बतायेगा लेकिन अभी तक रमाकांत भागव की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है।

हफ्ते का कार्टून



ट्वीट-ट्वीट

जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में एक डॉक्टर और प्रवासी मजदूरों समेत कई लोगों की हत्या बहुत ही कारगरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध है। सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi



जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया (OFK) में आज सुबह गीषण विस्फोट में दो कर्मचारियों की मृत्यु होने और 10 से ज्यादा लोगों के झुलसने का दुःखद समाचार मिला।



ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है।
ॐ शान्ति।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

स्कूल शिक्षिका से लेकर
देश के सर्वोच्च पद तक
पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

समता पाठक/जगत प्रवाह



द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई, 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पहले, वे, 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रहीं। उन्होंने अपना जीवन वंचित, पिछड़े और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए समर्पित किया है। 20 जून, 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में जन्मी मुर्मू का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा। गाँव के स्कूल से प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद, वे, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अपनी ही पहल पर भुवनेश्वर गईं। उन्होंने रमादेवी महिला महाविद्यालय, भुवनेश्वर से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे अपने गाँव से कॉलेज जाने वाली प्रथम बालिका बनीं। मुर्मू ने 1979 से 1983 तक ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्य किया। बाद में, 1994 से 1997 तक उन्होंने, श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर, रायरंगपुर में मानद शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दीं।

वर्ष 2000 में, मुर्मू रायरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र से ओडिशा विधान सभा की सदस्य के रूप में चुनी गईं और 2009 तक, दो कार्यकालों के लिए विधायक रहीं। इस अवधि के दौरान, उन्होंने 6 मार्च, 2000 से 6 अगस्त, 2002 तक ओडिशा सरकार के वाणिज्य और परिवहन विभाग की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में तथा 6 अगस्त, 2002 से 16 मई, 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विभाग की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्य किया। दोनों ही दायित्वों के निर्वहन में, उन्होंने अभिनव निर्णय लिए और लोकहितकारी कदम उठाए। उन्हें ओडिशा विधान सभा की विभिन्न समितियों व सदन समितियों और स्थायी समितियों का सदस्य नियुक्त किया गया। इनमें से कुछ समितियों की वे अध्यक्ष भी रही। अपने गहन प्रशासनिक अनुभव और आदिवासी समाज के उत्थान हेतु, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के बल पर, उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। विधायक के रूप में उनकी विशिष्ट सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, 2007 में उन्हें ओडिशा विधान सभा द्वारा 'पंडित नीलकंठ दास- सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान' से विभूषित किया गया।

द्रौपदी मुर्मू को, 18 मई, 2015 के दिन झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे, उस आदिवासी बहुल राज्य की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनीं। संविधान की गरिमा को अक्षुण्ण रखने तथा जनजातीय समुदायों के अधिकारों का समर्थन करने के लिए व्यापक रूप से उनकी सराहना की गई। उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में अनेक सुधार किए। राजनीतिक श्रुति और लोकतांत्रिक मूल्यों में अपनी निष्ठा के बल पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का आदर उन्होंने अर्जित किया। मुर्मू, ओडिशा के आदिवासी सामाजिक-शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के अनेक संगठनों से जुड़ी रहीं। स्वाध्याय में उनकी विशेष रुचि है और अध्यात्म में उनकी गहरी आस्था है।

प्रेम, समर्पण और त्याग का प्रतीक है करवाचौथ

जगत प्रवाह. भोपाल।

आज भागदौड़ भरे समय में रिश्तों के बीच संवाद घटता जा रहा है, हर व्यक्ति केवल स्वयं पर केंद्रित होकर आगे बढ़ रहा है लेकिन इन सबके बीच भी अगर विश्वास, त्याग और गहराई की बात की जाए तो पति-पत्नी का रिश्ता ही काफ़ी मजबूत नजर आता है। इसकी गहराई का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि हर रिश्ते का नाम लेने के लिए हमें दो शब्दों की जरूरत होती है, जैसे मां-बेटा, बाप-बेटी, भाई-बहन, चाचा-भतीजा लेकिन सिर्फ एक रिश्ता ऐसा है जो एक ही शब्द में बयां हो जाता है जीवनसाथी। इसी



आज की
बात
प्रवीण
कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

कारण इस रिश्ते को महत्वपूर्ण माना गया है। इसी रिश्ते के प्रति त्याग और समर्पण का प्रतीक है करवाचौथ। इस बार करवा चौथ व्रत 20 अक्टूबर को है। यह व्रत जहां पत्नी के पति के प्रति त्याग और समर्पण की भावना को बयां करता है, वहीं पति और पत्नी से भावनात्मक लगाव का भी परिचायक है।

करवाचौथ... पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में सदियों से मनाया जाने वाला यह पर्व आज पूरे भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार बन गया है। अगर भारत के बाहर का कोई व्यक्ति आकर इस त्यौहार को देख ले, तो वह निश्चित तौर पर इसे अत्यंत कठिन व्रत के तौर पर देखेगा लेकिन भारतीय महिलाएं जिस उत्साह और आस्था के साथ दिनभर निराहार और निर्जला रहकर यह व्रत रखती हैं, वह अपने आप में बहुत ही विलक्षण बात है। दिन भर जल ग्रहण ना करना और शाम को चंद्रमा को अर्ध चढ़ाकर पति के हाथ से पानी पीना बहुत ही श्रम साध्य काम है।

व्रत की इस तपस्या और साधना के साथ ही

इसके इस पक्ष पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह दांपत्य की पवित्रता का भी पर्व है। भारतीय संस्कृति में माना भी गया है कि प्रेम का मूल तत्व त्याग है। ऐसे में इस तरह त्याग का प्रदर्शन करके महिला दांपत्य के उस रिश्ते को एक नई ऊंचाई और गहराई प्रदान करती हैं जो असल में तो पति और पत्नी के बीच हमेशा भी होना चाहिए। यह उनके रिश्ते में आई किसी भी तरह की जड़ता को तोड़ने का काम करती है।

आज सामूहिक परिवारों की तुलना में एकल परिवार बढ़ रहे हैं। ऐसे में पति-पत्नी पर स्वयं के करियर व एक-दूसरे से आपसी समझ के साथ ही भावी पीढ़ी को तैयार करने की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में जीवनसाथी की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना बेहद जरूरी है। भावनात्मक संबंध में यह सम्मान व विश्वास इस रिश्ते को खूबसूरत बनाए रखता है। हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा रहे त्यौहार व करवाचौथ जैसे व्रत खुशहाल वैवाहिक जीवन की नींव रखते हैं।

(शेष पेज 6 पर)

युद्ध का पर्यावरण पर होता है खतरनाक असर

जगत प्रवाह. भोपाल।

युद्ध और संघर्ष न केवल लोगों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अपने पहले वर्ष में, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने चेक गणराज्य की तुलना में अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न किया। गाजा में, पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश को पारिस्थितिकी विनाश और युद्ध अपराध के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। एक तरफ विश्व समुदाय पर्यावरण के प्रति चिंता जाहिर करते हैं तो दूसरी तरफ विश्व के हर हिस्से में कहीं न कहीं युद्ध होते रहते हैं जिससे पर्यावरण पर असर पड़ता है।

युद्ध और संघर्ष मानव सभ्यता के इतिहास का एक अटूट हिस्सा रहे हैं। चाहे वह प्राचीन काल के युद्ध हों या आधुनिक समय के संगठित और तकनीकी रूप से परिष्कृत युद्ध, इनका प्रभाव केवल मानव जीवन और समाज पर ही नहीं बल्कि पर्यावरण पर भी गहरा पड़ता है। युद्ध का पर्यावरण पर खतरनाक असर कई स्तरों पर देखा जा सकता है, जिसमें वनों का विनाश, जल स्रोतों का दूषित होना, जैव विविधता की हानि, वायुमंडलीय प्रदूषण और मिट्टी की उर्वरता का नष्ट होना शामिल है।

युद्ध के दौरान वनों का विनाश एक गंभीर समस्या है। जंगल और हरियाली युद्ध की गतिविधियों में सबसे पहले प्रभावित होते हैं। युद्ध की स्थितियों में भूमि के बड़े हिस्से को खाली करने के लिए पेड़-पौधों को काटा जाता है, जिससे जंगलों की भारी हानि होती है। युद्ध के दौरान वनों में आग लगाने या बमबारी करने के कारण लाखों हेक्टेयर वन भूमि नष्ट हो जाती है। यह केवल वनों के विनाश तक सीमित नहीं है, बल्कि उन क्षेत्रों में रहने वाले वन्य जीवों और अन्य जीवों की प्रजातियाँ भी खतरे में पड़ जाती हैं। जंगलों का विनाश केवल पेड़ों की



पर्यावरण
की फिक्र
डॉ. प्रशांत
सिन्हा

हानि नहीं है, बल्कि इससे पर्यावरणीय संतुलन भी बिगड़ता है। पेड़-पौधे न केवल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित करते हैं। जब वन नष्ट हो जाते हैं, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है।

युद्ध के दौरान जल स्रोतों का दूषित होना एक बड़ी समस्या है। रासायनिक हथियारों, बमबारी और विस्फोटकों के उपयोग से जल स्रोतों में हानिकारक रसायन मिल जाते हैं, जो न केवल जल को दूषित करते हैं, बल्कि मानव और वन्य जीवन के लिए भी खतरनाक होते हैं। उदाहरण के लिए, वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना ने 'एजेंट ऑरेंज' जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया, जिसने न केवल फसलों को नष्ट किया, बल्कि जल स्रोतों को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया। जब जल स्रोत दूषित हो जाते हैं, तो वह पीने योग्य नहीं रह जाते और इससे बीमारियों का प्रसार होता है। दूषित जल से कई तरह की जल जनित बीमारियाँ होती हैं, जो युद्धग्रस्त क्षेत्रों में पहले से ही खराब स्वास्थ्य सेवाओं के कारण और भी खतरनाक साबित होती हैं। युद्ध के कारण जैव विविधता की हानि एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है। बमबारी, भूमि में विस्फोटक सामग्री का उपयोग, और रासायनिक हथियारों का प्रयोग वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर देता है। कई प्रजातियाँ युद्ध के दौरान विलुप्त होने के कगार पर पहुँच जाती हैं। इसके अलावा, युद्ध के बाद पर्यावरण को पुनर्स्थापित करना एक लंबी प्रक्रिया होती है, और कई बार यह संभव भी नहीं हो पाता। कई बार युद्ध के दौरान दुर्लभ प्रजातियों का अवैध शिकार भी बढ़ जाता है, क्योंकि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में प्रशासन का नियंत्रण कमजोर हो जाता है। इससे वन्य जीवों की कई प्रजातियाँ विलुप्त के खतरे में पड़ जाती हैं। इसके अलावा, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों के बीच संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होता है। युद्ध के दौरान बमबारी और विस्फोटकों के उपयोग से मिट्टी की संरचना बुरी तरह प्रभावित होती है। विस्फोटक पदार्थों के कारण मिट्टी में भारी धातुएँ और हानिकारक रसायन मिल जाते हैं, जो उसकी

उर्वरता को नष्ट कर देते हैं। इससे कृषि उत्पादन में भारी गिरावट होती है, जो युद्ध के बाद खाद्य संकट को जन्म देती है। भूमि के बड़े हिस्से बंजर हो जाते हैं, और उनकी पुनः कृषि योग्य स्थिति में लौटने में वर्षों लग जाते हैं। इसके अलावा, युद्ध के दौरान भूमि की माइनिंग (बारूदी सुरंगें बिछाना) भी मिट्टी के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालती है। माइनिंग से न केवल मिट्टी की उपजाऊ परत नष्ट होती है, बल्कि यह भूमि को खतरनाक बना देती है, जिससे वहां खेती करना असंभव हो जाता है। युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर विस्फोटक सामग्री और रासायनिक हथियारों का उपयोग वायुमंडल में प्रदूषकों की मात्रा को बढ़ा देता है। बमबारी और गोलीबारी के कारण वायुमंडल में धूल, धुआँ और रासायनिक तत्व फैलते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। यह प्रदूषण केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हवा के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में भी फैलता है। इससे मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जैसे सांस की बीमारियाँ, त्वचा रोग और अन्य शारीरिक समस्याएँ आदि। वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है। युद्ध के कारण पैदा हुए वायु प्रदूषण से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो सकती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और गंभीर हो जाती है। परमाणु युद्ध का पर्यावरण पर सबसे विनाशकारी प्रभाव होता है। परमाणु विस्फोटों से उत्पन्न विकिरण (रेडिएशन) न केवल तत्काल प्रभाव से बड़े पैमाने पर विनाश करता है, बल्कि उसका प्रभाव वर्षों तक बना रहता है। परमाणु हथियारों के प्रयोग से वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ फैलते हैं, जो मृदा, जल और वायु को प्रदूषित करते हैं। इसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक देखा जाता है। रेडियोधर्मी विकिरण से पौधे, जानवर और मनुष्यों की स्वास्थ्य स्थितियों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इससे कैंसर जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा, परमाणु विस्फोटों से उत्पन्न धुआँ और धूल सूर्य की किरणों को अवरुद्ध कर सकते हैं, जिससे 'परमाणु सर्दी' जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जो पृथ्वी पर जीवन को खतरे में डाल सकती हैं। (शेष पेज 6 पर)

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान-

त्यार्थ की कवायद हैं एग्जिट पोल



प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ साहित्यकार व
पत्रकार

निर्वाचन आयोग ने 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र और 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में चुनाव की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। जबकि झारखंड में दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। साथ ही 15 राज्यों की 48 विधानसभा और दो लोकसभा सीटों पर 13 एवं 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। इनके नतीजे भी 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। केरल की चर्चित लोकसभा सीट वायनाड से कांग्रेस ने प्रियंका वाड़ा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यह सीट यहीं से चुने गए राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। राहुल वायनाड के साथ रायबरेली से भी चुनाव लड़े थे। दोनों जगह पर उन्होंने जीत हासिल की थी। इसलिए एक जगह से इस्तीफा देना जरूरी था। इन चुनावों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने एग्जिट पोल पर देश के मीडिया को आत्मचिंतन करते हुए जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत जताई है। साथ ही उन्होंने ईवीएम को मतदान के लिए पूरी तरह सुरक्षित बताया है।

दरअसल उन्हें यह सफाई इसलिए देनी पड़ी, क्योंकि जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के परिणाम घोषित होने के

बाद से ही एग्जिट पोल के आधार पर ईवीएम पर सवाल उठाने लगे थे। इस बात पर राजीव कुमार ने दो टूक कहा कि 'एग्जिट पोल बेमतलब है। उनका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि हाल के चुनावों में जो रुझान टीवी चैनलों पर शुरू में दिए गए वे पूरी तरह आधारहीन थे। जब आयोग की वेबसाइट पर साढ़े 9 बजे पहला रुझान दिया जाता है तो फिर टीवी चैनल मतगणना शुरू होने के 10-15 मिनट के भीतर कैसे रुझान शुरू कर सकते हैं? इसका नतीजा यह होता है कि ये रुझान भी एग्जिट पोल की तरह गलत साबित होते हैं। हो सकता है कि संवादाता मतदान केंद्र के आसपास खबरें जुटाते हों, लेकिन उनकी खबरें जल्दी ही एकदम उलट कैसे जाती हैं? इसका मतलब है कि चैनल ऐसे रुझान दिखाकर सिर्फ अपने एग्जिट पोल को सही ठहराने का प्रयास करते हैं।' वाकई 2024 के लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल अनुमानों के विपरीत निकले। ज्यादातर सर्वेक्षण एजेंसियों ने राजग गठबंधन को बड़े बहुमत से आने का दावा किया था। लेकिन स्वयं भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई है। यानी उसे स्वयं लोकसभा में बहुमत नहीं मिला। इधर हाल ही में जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल के अनुमान उल्टे पड़े हैं। हरियाणा में अनुमान कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत दिखा रहे थे, लेकिन भाजपा ने 49 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। अतएव विपक्ष ने एग्जिट पोल के आधार पर हरियाणा के नतीजों पर ईवीएम के जरिए सवाल खड़े कर दिए। विडंबना है कि विपक्ष वहां तो हल्ला करता है, जहां से उसे हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहां घात रहता है, जहां से उसे जीत मिलती है। एक तरह से यह दोगले पन की राजनीति है।

ढाई माह चले लोकसभा के चुनावी यज्ञ में मतदाताओं ने सात चरणों में तेज गर्मी के बावजूद अपने मत की आहुतियां दी थीं। हालांकि 2019 की तुलना में सभी चरणों में मतदान कम रहा था। अकसर कम मतदान को चुनावी विप्लेषक सत्तारूढ़ दल के विरोध में मतदाता का होना बताते हैं। यही अनुकरण एग्जिटपोल करते हैं। इसीलिए

मतदान के बाद एग्जिट पोल सर्वेक्षणों के खुलासे ने साफ कर दिया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी व अमित शाह की युगल जोड़ी जमीन पर रणनीतिक सफलता हासिल करने जा रही है। इस बार मोदी की आक्रामक शैली ने हिंदू वोटों को पूरे देश में जबरदस्त ढंग से धुंकी कर देने का काम किया है। जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चुनाव के दौरान भी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति का खेल खेलते रहे। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पिछड़े वर्ग के कोटे में मुसलमानों को आरक्षण देना महंगा पड़ा दिखाई देता है। मोदी ने इस मुद्दे को उछालकर न केवल इन प्रांतों में बल्कि पूरे देश में पिछड़े और अति पिछड़ों को अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति सचेत कर दिया है। नतीजतन इस वर्ग के मतदाताओं ने राजग को झोली भरकर वोट दिए हैं। इस मुद्दे को मोदी ने बंगाल में भी भुनाया है। इसी का परिणाम है कि 2019 में मिली 18 सीटों की तुलना में भाजपा को यहां 21 से 28 सीटें मिलने तक का अनुमान बताया था। राम मंदिर, धारा-370 और तीन तलाक जैसे मुद्दों ने सभी वर्ग के मतदाताओं को लुभाया है। दूसरे लाडली बहना, मुफ्त राशन, मुफ्त आवास, हर घर में नल से जल, स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुष्यमान योजना और स्त्री सुरक्षा के लिए शौचालय जैसी योजनाओं से मिले लाभ के चलते ग्रामीण मतदाता राजग के पक्ष में खुला खड़ा दिखाई दिया है। स्त्री मतदाता मोदी को चुनने में आगे दिखाई दे रही हैं। परंतु परिणाम आने के बाद सच्चाई से अवगत होने पर पता चला कि मीडिया की ये मुनादियां गलत साबित हुईं।

2019 की तुलना में मतदान कम रहने के बावजूद औसत मतदान 62 प्रतिशत से ऊपर रहा था। ये सर्वे यदि 4 जून को आने वाले वास्तविक नतीजों पर खरे उतरते तो राजग गठबंधन स्पष्ट बहुमत में आ जाता। यही नहीं ऐसा होता तो लोकसभा में बहुमत के लिए राजग को सहयोगियों की जरूरत नहीं पड़ती। ये अनुमान जता रहे थे कि दलित,

वंचित और वनवासी मतदाताओं का जातिगत मतदान से मोहभंग हो रहा है और वे क्षेत्रीय संकीर्णता से मुक्त हो रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में इन्हीं वर्ग से रामनाथ कोविंद और द्रोपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जाना भी भाजपा के पक्ष में परिणाम का जाना बता रहे थे।

एग्जिट पोल के चुनावी विशेषज्ञ यह भी घोषित कर रहे थे कि धर्मनिरपेक्षता के पैरोकारों पर सनातन-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हावी रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के प्रमुखों ने रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकराने का असर भी मतदाता पर पड़ा है। गोया लगता है, अब छद्म धर्मनिरपेक्षता का आवरण टूट रहा है। केवल बंगाल में ममता बनर्जी मुस्लिम मतदाताओं के तुष्टिकरण के इस छल का सहारा ले रही हैं। गौरतलब है कि इस बार बंगाल को फोकस करके भाजपा ने हमलावर रणनीति अपनाई है। नतीजतन जो वामपंथी एक समय कंधे पर लाल झंडा उठाए गौरव का अनुभव करते थे, वे भाजपा में शामिल होकर केसरिया झंडा थामे, जय-जय श्रीराम के नारे लगा रहे हैं। इन वामपंथियों ने जहां भाजपा को ताकत दी है, वहीं कम्युनिस्टों के रहे इस गढ़ को नेस्तनाबूद करने का काम भी कर दिया है। एक बार फिर यह मिथक बनता दिखाई दे रहा है कि उत्तरप्रदेश की राजनीतिक जमीन से ही प्रधानमंत्री का पद सृजित होगा। इसी मिथक को पुनर्स्थापित करने के लिए मोदी बनारस से चुनाव लड़े हैं। मोदी की यहां आमद ने पूरे पूर्वांचल को भगवा रंग में रंग दिया है। नतीजतन भाजपा यहां सर्वेक्षणों के अनुसार अच्छी स्थिति में है। स्पष्ट लग रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। किंतु परिणाम के बाद हमने देखा कि उग्र और बंगाल में मतदाता ने भाजपा को बड़ा झटका दिया और एग्जिट पोल के अनुमान धराशायी हुए। इससे लगता है कि राजीव कुमार ठीक ही कह रहे हैं कि एग्जिट पोल व्यर्थ की कवायद है। (जगत फीचर्स)

प्रेम, समर्पण और त्याग का प्रतीक है करवाचौथ

(पेज 5 का शेष)

व्रत और पर्व पति-पत्नी के बीच संवाद और स्नेह का जरिया बनते हैं। ऐसे अवसर वैवाहिक जीवन में आ रही कड़वाहट को दूर करने का सबसे सटिक माध्यम हैं। कभी करियर की भागदौड़ तो कभी स्वयं को सही सिद्ध करने की होड़ में पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति संयम खो बैठते हैं। कभी अहंकार तो कभी अविश्वास रिश्ते पर हावी होने लगता है। ऐसे में करवाचैथ का पर्व उन्हें एक-दूसरे के करीब लाता है। प्रेम और त्याग का अहसास कराता है।

इसलिए करवाचौथ सिर्फ पति और पत्नी के प्रेम का त्यौहार नहीं है, यह पारिवारिक रिश्ते की मिठास का त्यौहार भी है। अगर यह मिठास ना हो तो कोई महिला दिन भर भूखे प्यासे रहने के बाद शाम को इस तरह से सोलह सिंगार करके चंद्रमा और अपने पति की आरती नहीं कर सकती। अब तो कई पुरुष भी पत्नी का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ जोड़े से व्रत करने लगे हैं, ऐसे त्यौहारों की रचना भारतीय समाज ही कर सकता है और उनका निर्वाह भी।

युद्ध का पर्यावरण पर होता है खतरनाक असर

(पेज 5 का शेष)

युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर शरणार्थी बन जाते हैं। शरणार्थियों के लिए अस्थायी शिविरों

का निर्माण होता है, जो अक्सर प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन का कारण बनते हैं। वनों की कटाई, जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, और कचरे की बढ़ती मात्रा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। शरणार्थी संकट के कारण पर्यावरणीय क्षति को नियंत्रित करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तत्काल मानवीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है। युद्ध के बाद का पुनर्निर्माण भी पर्यावरण पर असर डालता है। नष्ट हुई इमारतों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को फिर से बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है। इसके अलावा, युद्ध के दौरान छोड़े गए मलबे और खतरनाक सामग्री का निपटारा एक बड़ी समस्या बन जाता है। इन मलबों में रासायनिक और विषैले तत्व होते हैं, जो लंबे समय तक पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं।

युद्ध का पर्यावरण पर खतरनाक असर न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी गंभीर चुनौतियां खड़ी करता है। युद्ध के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय क्षति को भरपाई करना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है, जिसमें कई बार सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि युद्ध के प्रभावों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर काम करना चाहिए। साथ ही, पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता और संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में मानवता और पर्यावरण को ऐसे विनाशकारी प्रभावों से बचाया जा सके।

कार्यालय नगरपालिका परिषद विदिशा म0प्र0

क्रमांक...../नामा.शाखा/2024/5123 विदिशा दिनांक 16/10/24

इस्तहार उज्जदारी-सूचना

सर्व साधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न भवन/प्लॉट/दुकान के स्वामियों द्वारा नामांतरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिनका विवरण निम्न है।

क्र.	आवेदक का नाम एवं पिता का नाम व पता	नामांतरण हेतु भवन/प्लॉट का विवरण	प्र.क्र.
1	श्री गुरुचरण मालवीय पुत्र श्री श्यामलाल मालवीय नि विदिशा	भवन 600 वर्गफिट राजमेया कालोनी वार्ड 33 विदिशा	1603x7 2024
2	श्री ताराचंद अहिरवार पुत्र श्री हल्कराम अहिरवार नि विदिशा	भूखण्ड 1054 वर्गफिट गोदावरी ग्रीन वार्ड क्र 37 विदिशा	1604x7 2024
3	श्रीमति नसरीन कुरेशी पत्नी श्री सईद कुरेशी नि विदिशा	भवन 600 वर्गफिट खरी फाटक बाहर वार्ड 30 विदिशा	1605x7 2024
4	श्री वेदप्रकाश मेहरा पुत्र श्री रज्जुलाल मेहरा नि विदिशा	भवन 2125 वर्गफिट टीलाखेडी नई बस्ती वार्ड 39 विदिशा	1606x7 2024
5	श्रीमति कृष्णा देवी पत्नी श्री चन्दन सिंह राजपूत नि विदिशा	भवन 630 वर्गफिट राजीव नगर वार्ड 27 विदिशा	1607x7 2024
6	श्रीमति माया कुशवाह पत्नी श्री कल्लू कुशवाह नि विदिशा	भवन 533.2 वर्गफिट खिरिया रोड वार्ड 25 विदिशा	1608x7 2024
7	श्रीमति सुमनलता जैन पत्नी श्री प्रमोद कुमार जैन नि विदिशा	भूखण्ड 1200 वर्गफिट रायपुरा नई बस्ती वार्ड क्र 10 विदिशा	1609x7 2024
8	श्रीमति शुभे सक्सेना पत्नी श्री सुधीर कुमार, श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री मधुसूदन सक्सेना नि विदिशा	भूखण्ड 2424.7 वर्गफिट पूरनपुरा गली न 05 वार्ड क्र 37 विदिशा	1610x7 2024
9	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री फूलसिंह कुशवाह नि विदिशा	भूखण्ड 1200 वर्गफिट जतरापुरा नदी रोड वार्ड क्र 07 विदिशा	1611x7 2024
10	श्रीमति सविता अग्रवाल पत्नी श्री शिवेश सिंह नि विदिशा	भवन 1363.15 वर्गफिट नवबाना वार्ड 17 विदिशा	1612x7 2024
11	अजरा निशा पत्नी श्री फिरोज खां नि विदिशा	भूखण्ड 1392 वर्गफिट पेडी स्कूल के पीछे खाई वार्ड क्र 12 विदिशा	1613x7 2024
12	श्री रामकपाल पुसाम पुत्र श्री फूलसिंह पुसाम नि विदिशा	भूखण्ड 800 वर्गफिट इन्द्र प्रस्थ कालोनी वार्ड क्र 35 विदिशा	1614x7 2024

अतः उक्त भवन/प्लॉट/...पर किसी को कोई आपत्ति हो तो 30 दिवस के अन्दर कार्यालय समय पर उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अन्यथा अवधि समाप्त होने के उपरान्त नगरपालिका के रजिस्टर में उक्त नाम दर्ज कर लिया जावेगा। बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद विदिशा

विष्णुदेव सरकार के राज में छत्तीसगढ़ की जनता को आखिर कब मिलेगा न्याय?

(पेज 1 का शेष)

हास्यास्पद बात यह है कि पिछले कोई 10 महीने में ईओडब्ल्यू और एसीबी सिर्फ पुराने प्रकरणों में दागियों को अभयदान दे रहा है, जैसे कि रिटायर्ड आईपीएस मुकेश गुप्ता एवं अन्य को अवैध तरीके से फोन टैपिंग प्रकरण एवं अन्य प्रकरणों को अवैध रूप से नस्तीबद्ध कर दिया गया है। ईओडब्ल्यू और एसीबी अपनी ही बिरादरी के आईपीएस अधिकारी जो पूर्व सरकार के घोटालों में शामिल रहे हैं उन पर तो कोई कार्यवाही करते नहीं दिख रही है, यह वही अधिकारी थे जिन्होंने उस समय भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं पर कहर बरपाया था। यह सब आज बड़ी ही बेशर्मी से वह सब भुला दिया गया है। 10 महीने की भाजपा सरकार में बड़ा प्रश्न यह उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ की असली सरकार कौन है। क्या भारत का सबसे अमीर आदमी दिल्ली में बैठकर सरकार चलवा रहे हैं या बैच ऑफ 2005 असली सरकार है। छत्तीसगढ़ सरकार में सभी लोग पावरफुल नजर आ रहे हैं और सभी अपनी मनमर्जियां से सरकार चला रहे हैं। जैसे मोदी जी का कैपेन था हर घर तिरंगा वैसे ही छत्तीसगढ़ में हर मंत्री, बैच ऑफ 2005, उद्योगपति समेत हर कोई मुख्यमंत्री नजर आ रहा है।

छत्तीसगढ़ में नौकरशाही पर साय सरकार कस रही शिकंजा छत्तीसगढ़ में नौकरशाही पर एक बार फिर राज्य की बीजेपी सरकार ने अपना शिकंजा कस दिया है। राजनीति के जानकार तस्दीक करते हैं कि जिस तर्ज पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जूनियर अधिकारियों पर भरोसा कर सरकार का संचालन कर रहे थे ठीक उसी तर्ज पर मौजूदा बीजेपी सरकार की स्थिति बनती जा रही है। दो राय नहीं कि मोदी की गारंटी का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में जनता की नजरों में खरे उतरे हैं लेकिन नौकरशाही जिस तरीके से बीजेपी सरकार पर हावी है उससे साफ होता है कि एक बार फिर राज्य में कांग्रेस के दिन फिरने वाले हैं। मतलब साफ है यदि नौकरशाही के इशारों पर सरकार का संचालन आगे भी जारी रहा तो सरकार के सामने कई गंभीर चुनौतियां आ सकती हैं। जिसमें सरकार की साख पर बड़ा लगने के आसार बढ़ गये हैं। बताया जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस को बैठे बिठाये जिस तरह से मुद्दे हाथ लग रहे हैं उसके चलते बीजेपी को विपक्ष के सामने जवाब देना मुश्किल हो रहा है। मुख्यमंत्री साय के 10 माह के कार्यकाल में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस को अपनी राजनीति चमकाने का मौका बैठे बिठाये दे दिया है।

सीमेंट के दाम बढ़ाकर बड़ी हुई कीमतें वापस लेना

छत्तीसगढ़ सीमेंट उद्योग के लिए हब साबित हुआ है। राज्य में शायद ही कोई ऐसी नामी गिरामी उत्पादक कंपनी न हो जिसका प्लांट कार्यरत न हो। हाल ही में सीमेंट कार्टेल कंपनियों ने इसके दाम में एक मुश्त 50 रुपये की बढ़ोत्तरी कर दी थी। राज्य में यह पहला मौका था जब सीमेंट के बाद में एक मुश्त 5-10 रुपये नहीं बल्कि सीधे तौर पर 50 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई थी। इस बढ़ोत्तरी के खिलाफ कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था। देखते ही देखते सरकार ने 45 रुपये की मूल्य की वृद्धि वापस ले ली। मात्र 05 रुपये की बढ़ोत्तरी को सीमेंट कार्टेल कंपनियों द्वारा स्वीकार किया गया। ऐसे में विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि प्रति सीमेंट बैग 45 रुपये आखिर किसके जेब में जाने वाले थे। कांग्रेसी नेता चरणदास महंत के मुताबिक सीमेंट उत्पादक कंपनियों से सालाना करोड़ों की उगाही का प्लान तैयार किया गया था। महंत की मुताबिक कांग्रेस के दबाव में बीजेपी सरकार ने बड़ी हुई दरें वापस ले लीं। हालांकि सीमेंट के दाम में अचानक 50 रुपये बढ़ोत्तरी के खिलाफ रायपुर के सांसद वृजमोहन अग्रवाल ने भी केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर

बड़ी हुई दरें वापस लेने की मांग की थी। उन्होंने भारत सरकार को लिखे पत्र में स्पष्ट किया था कि सीमेंट के दाम बढ़ने से आम नागरिकों के घरों के निर्माण का सपना आधा अधूरा रह जायेगा। इसका सीधा असर प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी पड़ेगा। गरीबों और आम नागरिकों के लिए घर बनाना महंगा साबित होगा। इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर विपक्ष भारी पड़ा है।

स्टील उद्योगों को सालाना 300 करोड़ की सब्सिडी

स्टील उद्योगों को 300 करोड़ की सब्सिडी रोकने के मामले में भी बीजेपी सरकार को फजीहत का सामना करना पड़ा है। राज्य सरकार को स्टील उद्योग को मिलने वाली सस्ती बिजली पर सब्सिडी फिलहाल रोक दी है। लेकिन गृहमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर सब्सिडी वाले मामले को और अटका दिया है। यह भी तथ्य सामने आया था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्टील उद्योगों को सालाना 300 करोड़ की सब्सिडी देकर उनके संगठनों के माध्यम मोटा माल वसूल लिया करते थे। इस मामले में कांग्रेस की चाल में राज्य की सरकार बुरी तरह से फंस गई। कांग्रेस ने सब्सिडी यथावत जारी रखने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन किया था लेकिन राज्य सरकार उद्योगपतियों और कांग्रेस को यह समझाने में विफल रही कि सब्सिडी किसी व्यक्ति तथा संस्था को सिर्फ एक बार दी जाती है। हर साल किसी भी उद्योग धंधे को बिजली मुहैया कराने में सब्सिडी नहीं दी जा सकती। उद्योग जगत के जानकार तस्दीक करते हैं कि स्टील उद्योगों को राज्य सरकार औद्योगिक इकाई निर्माण करने के दौरान पहले ही कई मामलों में सब्सिडी प्रदान कर चुके हैं। सरकारी तिजोरी पर सालाना हाथ साफ करके इस मामले में शासन को 300 करोड़ हर माह गंवाने पड़ते थे। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री इसमें हिस्सेदार हो जाते थे। मुख्यमंत्री साय ने सरकारी तिजोरी पर सालाना पड़ने वाले भार को एक ही झटके में खत्म कर दिया। इस मामले में उनका अच्छा प्रयास भी सरकार को अपेक्षित परिणाम नहीं दिला सका। सब्सिडी का मामला अभी भी लटका होने के चलते बीजेपी की किरकिरी हो रही है जबकि कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिला है।

कानून व्यवस्था पर पकड़ होना जरूरी

छत्तीसगढ़ में साय सरकार की नौ माह के कार्यकाल को लेकर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। प्रदेश में बीजेपी सरकार के गठन के तीन माह भी पूरे नहीं हो पाये थे कि कांग्रेस में प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने का मुद्दा उठाकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया था। बावजूद इसके कानून व्यवस्था में कसावट लाने में गृहमंत्री कमजोर साबित हुए। गृहमंत्री कानून व्यवस्था को संभालने में असफल हो रहे हैं। कानून व्यवस्था को बनाये रखने का काम गृहमंत्री का होता है। दूसरी ओर अधिकारियों के ट्रांसफर आमतौर पर नई सरकार के गठन के बाद जोरों पर होते हैं। लेकिन राज्य में न तो मुख्य सचिव बदला और न ही अलबत्ता तीन वर्ष पूर्व रिटायर्ड डीजीपी का कार्यकाल बढ़ाकर लगातार उपकृत किया जाता रहा। मौजूदा डीजीपी अशोक जुनेजा के बारे में स्पष्ट है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री बघेल द्वारा भी लगातार उपकृत होते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की हॉ में हॉ मिलाने के चलते मौजूदा बीजेपी सरकार में भी उनकी दखलअंदाजी बताई जाती है। नतीजन योग्य और वरिष्ठ अधिकारी होते हुए भी राज्य में संविदा पर डीजीपी पद पर बैठे हैं। कई जिलों के पुलिस अधीक्षक बेलगाम हैं। इन जिलों में अपराधिक घटनाओं को लेकर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। बालोदा बाजार के बाद कवर्था में भी हत्याकांड और आगजनी जैसी घटनाएं सामने आयी हैं। इन मामलों को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नियुक्त मुख्य सचिव को अभी तक नहीं बदले जाने के चलते भी प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं हुई है। मंत्रालय में सरकार का कार्यकाल बाधित होने का कारण भी मंत्रालयों के गलियारों में अफसरों की जुबान पर है। बताया जाता है कि कई जिलों के कलेक्टर मनमानी पर उतर आये हैं। राज्य में बालोदा बाजार कांड और कवर्था काण्ड को लेकर दोनों ही जिलों के कलेक्टर एसपी का तबादला कर राज्य

सरकार ने त्वरित कार्यवाही की। लेकिन यह कार्यवाही भी महज खानापूति साबित हुई। ऐसी नौबत क्यों आयी? इस ओर कोई मंथन नहीं किया गया। बताया जाता है कि प्रदेश में पहली बार कलेक्टर एसपी कांफ्रेंस से गृहमंत्री नदारद रहे। ठोस प्रशासनिक क्षमता का परिचय देने के बजाए फैसला लेने में देरी और कानूनी खामियां बरते जाने से कांग्रेस को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। ऐसे मुद्दों को वो लपककर बीजेपी की राजनीति पृष्ठभूमि पर हमले पर हमला कर रही है।

जूनियर अधिकारियों का बोलबाला

राज्य में बीजेपी सरकार को मुश्किल में डालने के मामले 2005 बैच के अखिल भारतीय सेवाओं के 'ज्वलनशील' अधिकारियों की भूमिका सामने आयी है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ कतिपय प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली सुखियों में है। इन अफसरों के बीच पावर पालिटिक्स का सीधा असर कानून व्यवस्था पर पड़ते नजर आ रहा है। राज्य सरकार के कामकाज पर निगाहें रख रहे कई पत्रकार तस्दीक करते हैं कि जूनियर अधिकारियों का समूह सीनियर अधिकारियों पर भारी पड़ रहा है। यही कारण है कि सत्ता और संगठन के बीच लगातार खाई खिंची जा रही है। दरअसल विपक्ष में रहते बीजेपी ने जिन आल इंडिया सर्विस के अधिकारियों की शिकायत केन्द्र सरकार से तो कभी चुनाव आयोग से की। वही अफसर मौजूदा नौकरशाही में लूप लपटा साबित हो रहे हैं। पत्रकार तस्दीक करते हैं कि सरकार के कामकाज और फैसलों में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के विश्वास पात्र अधिकारियों का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है। नतीजन राज्य सरकार के लिए उसका ही फैसला गले की फांस बनता जा रहा है। सरकार कई फैसलों को एक ओर मंजूरी देती है वहीं कांग्रेस के सड़कों पर उतरते ही उन फैसलों को वापस ले लेती है। बिलासपुर कमिश्नर के पद पर पहले एक अधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी होना, फिर चंद घंटों बाद उस आदेश का निरस्त हो जाना, फिर इस पद पर महिनो तक किसी दूसरे अफसर की नियुक्ति न होना राज्य की सरकार प्रशासनिक कमजोरी बयां कर रही है।

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सफल रहा भाजपा सदस्यता अभियान

बहरहाल प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर अपनी जड़े जमाने में जुटी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव और आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उठापटक जारी है। इस बीच सरकारी निगम मंडलों में नियुक्तियों का दौर भी शुरू हो गया है। राज्य महिला आयोग समेत अन्य निगम मंडलों में हो रहा मनोनयन बीजेपी के लिये उत्साहजनक साबित हो रहा है। ऐसे समय पार्टी की सदस्यता अभियान ने भी जोर पकड़ लिया है। चंद दिनों में ही बीजेपी ने ये सदस्यों की संख्या 36 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। लिहाजा माना जा रहा है कि जनता के बीच संतोषजनक साबित हुआ है।

मोहन सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल

(पेज 1 का शेष)

इसके अलावा एआईसीसी महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष अपने-अपने समर्थकों के साथ उपवास में शामिल हुए। बता दें प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार के विरोध में कांग्रेस द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किए जा रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए 05 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में मशाल जुलूस निकाला गया। जबकि 07 अक्टूबर को कैडल मार्च, 08 अक्टूबर को ब्लॉक स्तरीय उपवास एवं कन्या पूजन किया गया। 14 अक्टूबर को बेंटी बचाओ ज्ञापन दिया गया।

महिलाओं पर अपराध पर पूछे सवाल

बीते साल प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध के 32,765 अपराध घटित हुए। बीते कुछ महीनों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे महानगर में छोटी बच्चियों के साथ रेप की कई वारदातें हुईं। जाहिर है ऐसे में विपक्ष बिगड़ती

कानून व्यवस्था के जरिए सरकार पर हमला बोलेगा ही। हो सकता है प्रदेश में अगले महीने सूबे के विजयपुर और बुधनी में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस इस विरोध को ज्यादा हवा दे रही हो। लेकिन, सवाल तो यह भी है कि यदि अपराध हो रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक अपराधी कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर ऐसी जघन्य वारदातों को अंजाम देते रहेंगे? क्या सरकार इसके लिए निर्णायक कदम उठाएगी?

महिलाओं पर अत्याचार का गढ़ बन गया मध्य प्रदेश- कमलनाथ

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश दिन-प्रतिदिन महिलाओं और बच्चियों के लिए असुरक्षित प्रदेश बनता जा रहा है। पिछले दो महीने में जिस तरह से बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार एवं सामूहिक दुष्कर्म के समाचार मीडिया में आ रहे हैं, उससे महिला सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर खतरा खड़ा हो गया है। समाचार इतने भयानक हैं कि महु में सेना की सुरक्षा वाले इलाके में सेना अफसरों के साथ मौजूद युवतियों से बलात्कार की घटना सामने आती है। भोपाल में स्कूल में छोटी बच्ची दरिंदगी का शिकार होती हैं। छतरपुर में बलात्कारियों के हासले इतने बढ़ जाते हैं कि वह पीड़िता के घर में घुसकर परिजनों को गोली मार देता है और खंडवा में घर के बाहर खड़ी बलात्कार पीड़िता के ऊपर आरोपी का बेटा पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। 24 सितंबर को प्रदेश के चार शहरों जबलपुर, रीवा, मैहर और दतिया से सामूहिक बलात्कारों की खबर सामने आती है। इन सब घटनाओं के बीच मध्यप्रदेश की सरकार कुंभकरण की नींद सो रही है और महिला सुरक्षा के लिए कोई भी ठोस उपाय अब तक नहीं किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जारी बयान में यह बात कही।

बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर

कमलनाथ ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं से बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। इस अवधि में मध्य प्रदेश में बलात्कार के 3029 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा 3049 महिलाएं छेड़खानी का शिकार हुईं और 1445 महिलाएं शारीरिक शोषण का शिकार हुईं। प्रदेश में पोस्को से जुड़े अपराधों में 5951 मामले दर्ज किए गए इनमें से बलात्कार के 3641 मामले हैं। महिलाओं और नाबालिग से हुए बलात्कारों को देखें तो प्रदेश में हर दिन 18 बलात्कार हो रहे हैं।

मध्य प्रदेश के दो पूर्व सीएम भोपाल में धरने पर बैठे

मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री लंबे समय बाद एक मंच पर दिखाई दिए। एमपी कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जुगलबंदी एक बार फिर से दिखी। मौका था कांग्रेस के प्रदर्शन का। दरअसल, राज्य में बढ़ते महिला अपराध, यौन प्रताड़ना और नशे के कारोबार के खिलाफ कांग्रेस ने सामूहिक उपवास शुरू किया है। इस सामूहिक उपवास में पार्टी के सभी सीनियर नेता मौजूद हैं।

राहुल गांधी ने कमलनाथ से की थी मुलाकात

हाल ही में दिल्ली में राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी खुद कमलनाथ से मुलाकात करने के लिए उनके बंगले में पहुंचे थे। जिसके बाद से अटकलें लग रही थीं कि कमलनाथ को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।

दिग्विजय सिंह लगातार एक्टिव- वहीं, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार एक्टिव हैं। दिग्विजय सिंह राज्यभा सांसद हैं और वह राज्य के अलग-अलग जिलों का दौरा करते रहते हैं। हालांकि मंच पर दिग्विजय और कमलनाथ आपस में लंबी चर्चा करते दिखे। इन दोनों नेताओं की जुगलबंदी पर सियासत फिर से तेज हो गई है।

कलम के सिपाही...

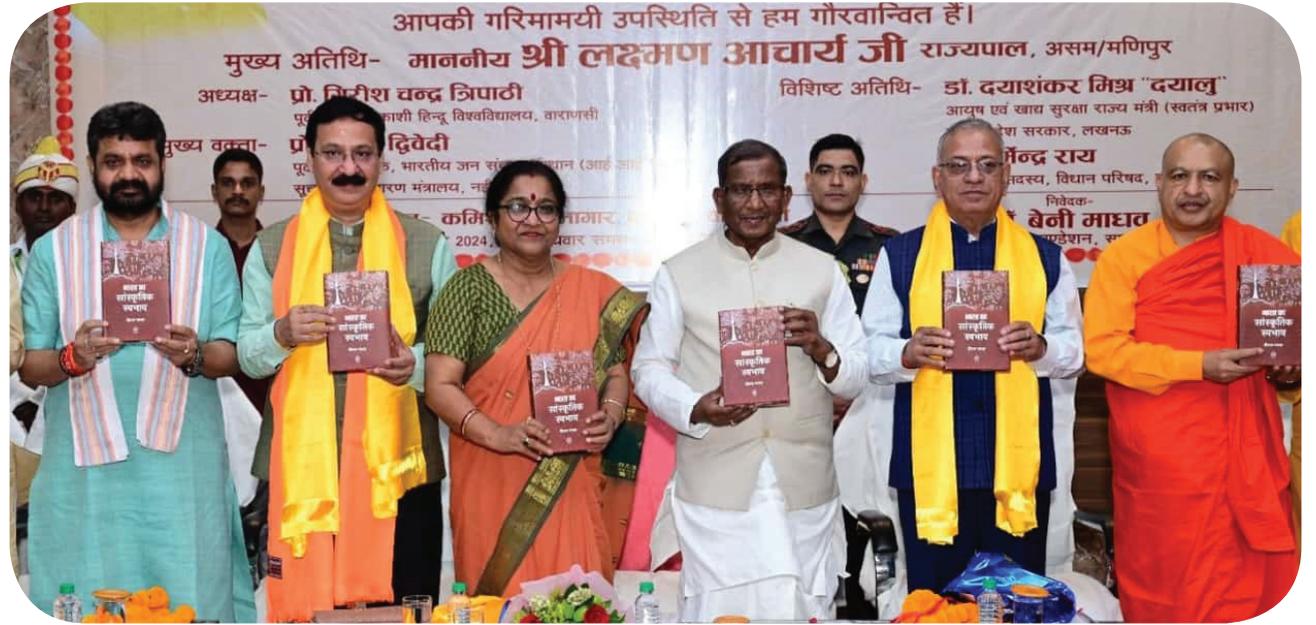
देश के प्रतिष्ठित खेल पत्रकार और एंकर हैं विक्रांत गुप्ता



विक्रांत गुप्ता एक भारतीय न्यूज एंकर हैं, जो कि आज तक पर अपने क्रिकेट से जुड़े कार्यक्रमों के लिए मशहूर हैं। विक्रांत गुप्ता की स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के बीच काफी अच्छी पहचान है। विक्रांत गुप्ता ने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस पर एक रिपोर्टर के रूप में की थी। आज विक्रांत देश के सबसे प्रसिद्ध स्पोर्ट्स एंकर के रूप में जाने जाते हैं। विक्रांत का जन्म 12 जनवरी 1973 को चंडीगढ़ शहर में हुआ था। विक्रांत गुप्ता ने अपनी शुरुआती पढाई चंडीगढ़ शहर से ही पूरी की जिसके बाद उन्होंने डीएवी कॉलेज से इंग्लिश में बीए की डिग्री हासिल की। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में मास्टर्स भी किया है। पत्रकारिता में करियर बनाने के लिए विक्रांत ने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की है। विक्रांत ने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस पर एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर के तौर पर की थी। कुछ साल बाद उन्होंने यह जॉब छोड़ आज़तक पर स्पोर्ट्स रिपोर्टर ज्वाइन कर लिया। खेल को दिल से समझना हो या दिमाग से, एक चेहरा जो जेहन में घूमता है वो है विक्रांत गुप्ता का। क्रिकेट की बारीकियां हों या फिर पर्दे के पीछे का खेल, नतीजे का पूर्वानुमान हो या फिर खिलाड़ी के दिल का हाल, विक्रांत गुप्ता का सटीक विश्लेषण एक सुलझे हुए पत्रकार की परिभाषा को बयां करता है। विक्रांत ने 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के साथ खुशी के पल भी बिताए। बतौर पत्रकार विक्रांत पांच वर्ल्ड कप कवर कर चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट की गंभीरता से लेकर ट्वेंटी-20 के रंग के साथ जीना विक्रांत का पेशा ही नहीं, शौक भी है।

विक्रांत गुप्ता देश के नंबर वन क्रिकेट शो के साथ आज़तक पर हर शाम 7.30 बजे दर्शकों से रुबरु होते हैं। वे यूट्यूब पर रात 8 बजे स्पोर्ट्स तक पर भी चर्चा में शरीक होते हैं। उनके जुनून, उनकी ऊर्जा को टेलिविजन न्यूज इंडस्ट्री ने भी सराहा और सम्मानित किया है, उन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स एंकर का पुरस्कार मिला है, साथ ही उनके कार्यक्रम को वेस्ट स्पोर्ट्स शो का अवॉर्ड भी। पहले अखबार में उनकी लेखनी और बाद में टेलीविजन में उनके तेवरों ने खेल पत्रकारिता को अलग ही आयाम प्रदान किए। मुहम्मद अजहरुद्दीन से लेकर सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली से लेकर महेंद्र सिंह धोनी और अब विराट कोहली तक भारतीय कप्तानों की कई पीढ़ियों को कवर चुके विक्रांत भारतीय क्रिकेट के कई ऐतिहासिक लम्हों के गवाह रहे हैं।

नीरजा माधव की पुस्तक लोकार्पण में बोले असम के राज्यपाल भारत में चल रही सांस्कृतिक पुर्नजागरण की लहर



-संवाददाता

जगत प्रवाह. वाराणसी। प्रख्यात लेखिका डॉ. नीरजा माधव की सद्यः प्रकाशित पुस्तक 'भारत का सांस्कृतिक स्वभाव' का लोकार्पण करते हुए असम एवं मणिपुर के राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि जिस तरह से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना स्वान्तः सुखाय की थी लेकिन कालांतर में रामचरितमानस पूरे देश ही नहीं विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग दिखाने वाला महाकाव्य बन गया। इसी तरह से नीरजा माधव ने भी अपनी संतुष्टि के लिए और भारतबोध की भावना के साथ इस पुस्तक की रचना की है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक पूरे राष्ट्र के लिए और समाज के लिए संतुष्टि प्रदान करने वाली बनेगी। वे यहां वाराणसी के कमिश्नरी सभागार में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि की आसंदी से बोल रहे थे।

कार्यक्रम में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के पूर्व कुलपति प्रो.जीसी त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डा. दयाशंकर मिश्र 'दयालु', भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के पूर्व महानिदेशक प्रो.संजय द्विवेदी, उप विधान परिषद के सदस्य डा.धर्मेंद्र राय, जम्मू दीप बौद्ध मंदिर के विहारधिपति डा.सिरी सुमेध थरो भी उपस्थित रहे।

राज्यपाल श्री आचार्य ने आगे कहा कि हाल के वर्षों में भारत में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लहर चल रही है। अपने अतीत से लोग फिर से परिचित होना चाह रहे हैं। नीरजा माधव की यह कृति भारत की सांस्कृतिक विरासत से लोगों का पुनः परिचय कराने का एक सशक्त आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि भारत को जानने की जिज्ञासा रखने वालों के लिए यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जो लोग दूर दराज से भारत को समझना चाहते हैं, उसकी सांस्कृतिक विरासत से परिचित होना चाहते हैं, उनके लिए "भारत का सांस्कृतिक स्वभाव" पुस्तक एक आवश्यक पुस्तक है।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में बीएचयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर जी.सी. त्रिपाठी ने कहा कि जब किसी भूखंड पर जीव सृष्टि का निर्माण होता है तो

उसे देश की संज्ञा मिलती है। जब वह जीव सृष्टि अपने साथ एक दर्शन, दृष्टि, विचार और मूल्यों के साथ कुछ सिद्धांतों और परंपराओं को अंगीकार करता है तब उसे राष्ट्र की संज्ञा मिलती है। नीरजा माधव ने अपने अथक प्रयास से भारत की संस्कृति और उसके स्वभाव को, भारत ने अपनी जीवन पद्धति, रीति रिवाज, व्यवहार, परंपरा और त्योहार आदि के माध्यम से अनादि काल से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे कायम रखा, इस पर महान कार्य किया है। यह ग्रन्थ साहित्य और साहित्यकार के धर्म का प्रतिनिधित्व करता है।

कार्यक्रम के मुख्यवक्ता भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि साहित्य का मूल उद्देश्य ही लोकमंगल है। पिछले कुछ वर्षों में भारत अपनी जड़ों की तरफ वापसी कर रहा है। यह विचारों की घर वापसी का समय है। इसीलिए साल तक चले समाजतुड़क साहित्यिक अभियानों के बजाय अब समाज को जोड़ने वाले तथा भारत बोध कराने वाले साहित्य की आवश्यकता है। नीरजा माधव जी की यह किताब भारत को समझने की कुंजी है। इससे भारत विकसित भारत बनेगा और अपने सपनों में रंग भरेगा।

उप सरकार में आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र "दयालु" ने अपने गंभीर और विचारपरक उद्बोधन में कहा कि नीरजा जी की यह पुस्तक काशी से कश्मीर तक की और कन्याकुमारी से काशी तक की यात्रा करवाती है। इस पुस्तक के अनुक्रम को देखने मात्र से पता चल जाता है कि कोई भी विषय छूटा नहीं है जो भारतीय संस्कृति को समझने के लिए आवश्यक है। यहां तक कि धारा 370 या कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की त्रासदी को भी नीरजा माधव ने बहुत ही संवेदना के साथ उकेरा है। विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र राय ने नीरजा माधव की इसी कृति को भारतीय साहित्य के लिए एक मील का पत्थर बताया। अपने लेखकीय उद्बोधन में साहित्यकार नीरजा माधव ने कहा कि भारतीय संस्कृति गंगा की तरह पवित्र और हिमालय की तरह बहुत विराट है लेकिन जैसे गंगा

का जल हथेली में लेकर पान करते ही पूरी गंगा हमारे भीतर उतर जाती है इसी तरह से भारतीय संस्कृति की झलक इस पुस्तक से मिल जाएगी। भारतीय संस्कृति से संबंध जुड़ने का तात्पर्य ही है कि पूरी धरती के उमंग से संबंध जुड़ना और आकाश के मंगल गान से जुड़ जाना। यह पुस्तक राष्ट्र से उसी तरह जुड़ने का प्रयास है।

पचमढ़ी और बनखेड़ी में आरटीओ ने की बसों की सघन जांच, 2 वाहन जप्त, 35 चालान से 50,600 वसूल

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। कलेक्टर के दिशा निर्देश अनुसार आरटीओ अधिकारी निशा चौहान के नेतृत्व में पचमढ़ी तथा बनखेड़ी में बसों के साथ साथ अन्य वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया गया। जिसमें यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बसों की सीटों, अग्नि शमन यंत्र, मेडिकल बाक्स, आपातकालीन खिड़की, अधिक किराया, ओवरलोडिंग आदि के अलावा वाहनों के दस्तावेजों, चालक- परिचालक के लाइसेंस, वर्दी आदि की जांच की गई। वर्मा ट्रेवलस की यात्री बस यात्री सुविधाओं को पूरा करती नहीं पर जाने पर बस पर चालानी कार्यवाही की गई तथा चालक को शीघ्र बस की कमियों को पूरा करने की चेतावनी आरटीओ अधिकारी द्वारा दी गई। दो दिवसीय सुबह से रात तक चली जांच में लगभग 200 वाहनों की जांच में 35 वाहनों पर चालानी कार्यवाही करते हुए 50600 रुपए के चालान काटे गए तथा अन्य 2 वाहनों को जप्त कर थाने में सुरक्षार्थ खड़ा करवाया गया। आरटीओ अधिकारी निशा चौहान ने बताया कि सभी वाहन स्वामी अपने वाहनों के दस्तावेजों को पूर्ण करवाकर ही वाहनों का संचालन करें, जांच दल में आरटीओ अधिकारी निशा चौहान के साथ समस्त जांच टीम रही।